



वर्ष-30 अंक : 170 (हैदराबाद, निजामाबाद, विशाखापट्टणम, तिरुपति से प्रकाशित) आश्विन कृ.9 2082 सोमवार, 15 सितंबर-2025

THE LARGEST CIRCULATED AND READ HINDI DAILY IN TELANGANA & ANDHRA PRADESH



epaper.vaartha.com
Vaartha Hindi
@Vaartha_Hindi
Vaartha official
www.hindi.vaartha.com

प्रधान संपादक - डॉ. गिरीश कुमार संधी हैदराबाद नगर ✽ पृष्ठ : 12 मूल्य : 8 रुपये

असम की जनसभा में बोले पीएम मोदी

मैं शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल जाता हूं

दरांग, 14 सितंबर (एजेंसियां)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर मिशन पर हैं। असम में उन्होंने 18,530 करोड़ रुपये से अधिक की प्रमुख बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। असम के दरांग में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कि वह भगवान शिव के भक्त हैं और दुश्मनों के द्वारा दिया गया सारा जहर निगल जाते हैं। पीएम मोदी ने यहां कांग्रेस पर जमकर हमला किया।

पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मेरा पहली बार असम आना हुआ है। मां कामाख्या के आशीर्वाद से ऑपरेशन सिंदूर को जबरदस्त सफलता मिली। इसलिए आज मां कामाख्या की धरती पर आकर एक अलग ही पुण्य अनुभव हो रहा है। आज यहां जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं :

मां के अपमान का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे कितनी ही गालियां दे, मैं भगवान शिव का भक्त हूं, सारा जहर निगल लेता हूं। लेकिन जब किसी और का अपमान होता है, तो मैं इसे बदलित नहीं कर सकता। आप लोग मुझे बताएं, क्या भूपेन दा को भारत रत्न से सम्मानित करने का मेरा निर्णय सही है या गलत? क्या कांग्रेस पार्टी द्वारा



उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए किया गया अपमान सही है या गलत? असम की ऐसी महान संतानों और हमारे पूर्वजों ने असम के लिए जो सपना देखा था, उसे पूरा करने में भाजपा की डबल इंजन सरकार पूरी निष्ठा से जुटी हुई है।

...उत्तर पूर्व के लोगों के घाव आज भी भरे नहीं :

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम पहले ही भारत रत्न सुधाकंठा भूपेन हजारिका जी का जन्मदिन मना चुके हैं। कल मुझे उनके सम्मान में आयोजित एक बहुत बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर मिला।

मुख्यमंत्री ने मुझे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का एक वीडियो दिखाया, और इसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। जिस दिन भारत

सरकार ने इस देश के महान सपूत, असम के गौरव, भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न दिया। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि मोदी नाचने-गाने वालों को भारत रत्न दे रहे हैं। 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद, पंडित नेहरू ने जो कहा, वह उत्तर पूर्व के लोगों के घाव आज भी भरे नहीं हैं।

कभी विकास के लिए संघर्षरत था असम :

पीएम मोदी ने असम में हो रहे विकास का जिक्र करते हुए कहा, भारत मौजूदा समय में दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है, और असम इसके सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक है। कभी विकास के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्षरत असम ने काफी बदलाव

किया है और अब 13 प्रतिशत की विकास दर के साथ उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। यह प्रभावशाली उपलब्धि यहां के लोगों के लचीलेपन और समर्पण का प्रमाण है। यह असम के लोगों की कड़ी मेहनत और भाजपा की दोहरी इंजन वाली सरकार के योगदान से प्रेरित, संयुक्त प्रयासों का भी परिणाम है।

आवारा कुत्तों पर विवाद के बीच पीएम मोदी बोले

एनिमल लवर्स गाय को जानवर नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स के पक्ष में फैसला सुनाया था

नई दिल्ली, 14 सितंबर (एजेंसियां)। देश भर में आवारा कुत्तों पर विवाद के बीच पीएम मोदी ने एनिमल लवर्स पर चुटकी ली। उन्होंने 12 सितंबर को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं पिछले दिनों कुछ एनिमल लवर्स से मिला। हमारे देश में ऐसे बहुत एनिमल लवर्स हैं और विशेषता है कि वे गाय को एनिमल नहीं मानते।

पीएम की बातों पर कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और हॉल में बैठे लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। प्रधानमंत्री भी मुस्कराने लगे और लोगों से उन्होंने पूछा- क्यों, आपको हंसी आ गई? पूरे वाकिये का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

दरअसल, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में दिल्ली-एनसीआर के आवासीय इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में हटकर हमेशा के लिए शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। इस आदेश का देश भर में डॉग लवर्स ने सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध किया था। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश पलट दिया। कोर्ट ने फैसले में संशोधन करते हुए आक्रामक या पागल कुत्तों को छोड़कर, सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीका लगाने के बाद वापस वहीं छोड़ने का आदेश दिया, जहां से उन्हें पकड़ा गया था।

पीएम आवास में गाय पालते हैं प्रधानमंत्री मोदी :

प्रधानमंत्री मोदी खुद एक गो प्रेमी हैं। वे दिल्ली के 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास में भी गाय पालते हैं। उन्होंने कई बार अपने आवास पर गायों के साथ समय बिताते पलों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।

पीएम मोदी ने जनवरी 2024 में, मकर संक्रांति पर पुंगनूर (गाय का ब्रीड) गायों को चारा खिलाते हुए अपना एक वीडियो साझा किया था। पुंगनूर छोटी कद की, बैलों की तरह दिखने वाली गायों की एक भारतीय नस्ल है।

गुलामी के कठिन दौर में भी भारतीय भाषाएं बनीं प्रतिरोध की आवाज : हिंदी ने पूरे किए 76 गौरवशाली वर्ष



नई दिल्ली, 14 सितंबर (एजेंसियां)। हिन्दी दिवस पर केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड चल रहा है। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाएं तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बनें। मिलकर चलो, मिलकर सोचो, मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है। डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में मोदी

सरकार भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम बना रही है।

शाह ने अपने संदेश में कहा, गुलामी के कठिन दौर में भी भारतीय भाषाएं प्रतिरोध की आवाज बनीं। आजादी के आंदोलन के राष्ट्रव्यापी बनने में हमारी भाषाओं की बड़ी भूमिका रही।

हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जनपदों की भाषाओं में, ग्राम-देहात की भाषाओं को आजादी के आंदोलन से जोड़ा। हिंदी के साथ ही सभी भारतीय भाषाओं के कवियों, साहित्यकारों और नाट्यकारों ने लोकभाषाओं में, लोककथाओं में, लोकगीतों और लोकनाटकों के माध्यम से हर आयु, वर्ग और समाज के भीतर स्वाधीनता के संकल्प को प्रबल बनाया। बन्दे मातरम् और जय हिंद जैसे नारे हमारी भाषाई चेतना से ही उपजे और स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान के प्रतीक बने।

अपना भारत मूलतः भाषा-प्रधान देश है। हमारी भाषाएं सदियों से संस्कृति, इतिहास,

परंपराओं, ज्ञान-विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की सशक्त माध्यम रही हैं। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गांव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहने और एकजुट होकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है। मिलकर चलो, मिलकर सोचो और मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई-सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है।

भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय को अभिव्यक्ति का अवसर दिया। पूर्वोत्तर में बीहू का गान, तमिलनाडु में ओवियालु की आवाज, पंजाब में लोहाड़ी के गीत, बिहार में विद्यापति की पदावली, बंगाल में बाउल संत के भजन, कजरी गीत, भिखारी ठाकुर की बिदेशिया, इन सबने हमारी संस्कृति को जीवंत और लोककल्याणकारी बनाया है।



नई दिल्ली, 14 सितंबर (एजेंसियां)। सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को नोटिस देते हुए कहा कि सरकारी लापरवाही को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मुकदमों को फाड़ल करने में अधिकारी को फाड़ल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करना अक्षमता को बढ़ावा देना है। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान यह बात कही।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाई कोर्ट को सरकार की लापरवाही को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। अगर सरकार देरी से कोई केस दोबारा

‘वोट चोरी के आरोपों की जांच के बजाय राहुल पर गुस्सा क्यों?’

पूर्व सीईसी ने की चुनाव आयोग की आलोचना

नई दिल्ली, 14 सितंबर (एजेंसियां)। विपक्षी इंडिया गठबंधन की तरफ से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों के चलते देशभर की सियासत में गर्माहट है। मामले में दोनों तरफ से आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति भी अपने चरम पर है।

ऐसे में देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरेशी ने मामले में आयोग की तरफ से आरोपों पर दी गई प्रतिक्रियाओं की आलोचना करते हुए पलटवार किया है। कुरेशी ने आयोग के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर चुनाव आयोग की गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय तथ्यों की जांच करवानी चाहिए थी।

राहुल के आरोपों पर आयोग की प्रतिक्रिया से जताई आपत्ति :

राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर आयोग की प्रतिक्रिया से आपत्ति जताते हुए कुरेशी ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, कोई आम नागरिक नहीं। उन्होंने लाखों लोगों की भावना को उठाया है, ऐसे में चुनाव आयोग को उनकी बात गंभीरता



खोलना चाहती है, तो कोर्ट को इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। इससे एक प्राइवेट व्यक्ति पर हमेशा तलवार लटक रहीगी। हाई कोर्ट के किस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी : कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के हाउसिंग बोर्ड को 11 साल की

देरी के बाद एक जमीन विवाद का केस दोबारा खोलने की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्याय के साथ मजाक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को चेतावनी दी है कि वे सरकार की तरफ से होने वाली अत्यधिक देरी को माफ न करें।

मेरे समय में विपक्ष को प्राथमिकता मिलती थी :

कुरेशी ने याद दिलाया कि जब वे मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने अपने कर्मचारियों को निर्देश दे रखा था कि विपक्षी नेताओं को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि वे सत्ता में नहीं होते और उनकी आवाज को भी सुना जाना चाहिए।

कुरेशी ने चुनाव आयोग को दी सलाह :

कुरेशी ने चुनाव आयोग से आत्मचिंतन की सलाह दी। साथ ही कहा कि अगर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, तो ये एक गंभीर संकेत है कि संस्थान को सुधार की जरूरत है। इसके अलावा पूर्व सीईसी ने राहुल गांधी से हलफनामा मांगने की आलोचना करते हुए कहा कि

चुनावी मौसम में बिहार को बड़ा तोहफा

पूरुणिया से पीएम देंगे 36 हजार करोड़ रुपये की सौगात पूरुणिया, 14 सितंबर (एजेंसियां)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को चुनावी राज्य बिहार के पूरुणिया जिले पहुंचेंगे। यहां वे एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और करीब 36 हजार करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम इस दौरान पूरुणिया में बने नए हवाई अड्डा टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। इस टर्मिनल से उत्तर बिहार को हवाई संपर्क की सुविधा मिलेगी, जिसकी लंबे समय से मांग हो रही थी। कार्यक्रम की एक अहम कड़ी राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन भी होगा। इसकी घोषणा इस साल के केंद्रीय बजट में की गई थी। प्रधानमंत्री कई बार अपने भाषणों में मखाना को सुपर फूड बता चुके हैं।

‘मैं कोई संत नहीं हूं’

आखिर नितिन गडकरी ने क्यों कही यह बात



मुंबई, 14 सितंबर (एजेंसियां)। इथेनॉल पर चल रही बहस के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने आलोचकों पर कटाक्ष किया। गडकरी ने कहा कि उनका दिमाग 200 करोड़ रुपये प्रति माह का है और वह वित्तीय लाभ के लिए किसी भी हद तक नहीं गिरेंगे। गडकरी की यह टिप्पणी इथेनॉल पर चल रही बहस की पृष्ठभूमि में आई है। जिसमें खाद्य एवं जल सुरक्षा तथा वाहन अनुकूलता पर चिंताओं के मुकाबले उत्सर्जन में कमी के लाभों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी पहल और प्रयोग विचारों से प्रेरित हैं और उनका उद्देश्य किसानों को लाभ पहुंचाना है, न कि व्यक्तिगत वित्तीय लाभ प्राप्त करना।

नागपुर में एग्रीकोस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि आपको लगता है कि मैं यह सब पैसे के लिए कर रहा हूं? मैं ईमानदारी से कमना जानता हूं। मैं कोई दलाल नहीं हूं।

गडकरी ने कहा कि राजनेता अक्सर अपने फायदे के लिए विभाजन का फायदा उठाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि पिछड़ापन एक राजनीतिक हथियार बन गया है।

उन्होंने कहा कि मेरा भी एक परिवार और एक घर है। मैं कोई संत नहीं हूं, मैं एक राजनेता हूं। लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि विद्वेष में लगभग 10,000 किसानों की आत्महत्या बेहद दर्दनाक है। जब तक किसान समृद्ध नहीं हो जाते, हमारे प्रयास जारी रहेंगे।

मंत्री की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर को सभी ईंधन स्टेशनों पर इथेनॉल युक्त पेट्रोल की अनिवार्य उपलब्धता की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज किए जाने के मद्देनजर आई है। केंद्र ने इस याचिका का विरोध करते हुए इसे राष्ट्रीय नीति को कमजोर करने का प्रयास बताया था।

भारत ने अप्रैल 2023 में देश भर में 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (ई20) लागू कर दिया, जिससे उसका मिश्रण लक्ष्य

निर्धारित समय से पांच वर्ष पहले ही पूरा हो गया।

इस कार्यक्रम को कार्बन उत्सर्जन कम करने और कच्चे तेल के आयात में कटौती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है, फिर भी इसने बहस छेड़ दी है। उपभोक्ताओं और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों सहित आलोचकों ने चेतावनी दी है कि इथेनॉल-मिश्रित ईंधन वाहन की दक्षता और स्थायित्व को प्रभावित कर सकता है।

याचिका में मिश्रित ईंधन के साथ-साथ इथेनॉल-मुक्त पेट्रोल की उपलब्धता सुनिश्चित करने, पंपों पर इथेनॉल की मात्रा का स्पष्ट लेबल लगाने तथा मिश्रित ईंधन के यांत्रिक प्रभाव पर राष्ट्रव्यापी अध्ययन कराने के निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता अक्षय मल्होत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत ने तर्क दिया कि याचिका इथेनॉल मिश्रण के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उपभोक्ता की पसंद को संरक्षित करना है।

उन्होंने कहा कि केवल अप्रैल 2023 के बाद निर्मित वाहन ही ई20 पेट्रोल के अनुरूप हैं, जबकि पुराने मॉडलों में ई 0 या ई10 विकल्पों के अभाव में यांत्रिक क्षति और उच्च रखरखाव लागत का जोखिम होता है।

अर्दानी जरलर आर. वेंकटरमणी ने याचिका का विरोध किए, तथा याचिकाकर्ता को नाम-उधार देने वाला बताया तथा सुझाव दिया कि यह मुकदमा निहित स्वाधों का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत के स्वच्छ ईंधन अभियान को पटरी से उतारने का प्रयास कर रहा है।





भारत सरकार

विकसित बिहार विकसित भारत



बिहार के लोगों के लिए विद्युत, रेलवे, एयरपोर्ट, आवासन एवं शहरी कार्य, जल शक्ति, ग्रामीण विकास, कृषि, पशुपालन तथा डेयरी क्षेत्रों की 36000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उपहार

शिलान्यास

- पीरपैंती (भागलपुर) में 3x800 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना • कोसी-मेची अंतर-राज्यीय नदी लिंक परियोजना फेज-I
 - बिक्रमशिला-कटरिया के बीच नई रेल लाइन (26 किमी)
- सुपौल तथा कटिहार जिलों में अवरोधन एवं विपथन (आई एंड डी) एवं अपशिष्ट शोधन संयंत्र (एसटीपी) कार्य
 - दरभंगा, कटिहार तथा भागलपुर में जलापूर्ति परियोजनाएं

उद्घाटन

- पूर्णिया हवाई अड्डे के अंतरिम टर्मिनल भवन • अररिया-गलगलिया (ठाकुरगंज) के बीच नई रेल लाइन (111 किमी)
- नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत भागलपुर में अपशिष्ट शोधन संयंत्र (एसटीपी) तथा अवरोधन एवं विपथन (आई एंड डी)
 - पूर्णिया में स्वदेशी गोजातीय लिंग-विभेदित वीर्य उत्पादन सुविधा

हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ

- पूर्णिया हवाई अड्डे से पहली वाणिज्यिक उड़ान
- अररिया-गलगलिया नई रेल लाइन से होकर जाने वाली कटिहार-सिलीगुड़ी एक्सप्रेस • जोगबनी-दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस
 - सहरसा-छेहरटा (अमृतसर) अमृत भारत एक्सप्रेस • जोगबनी-इरोड अमृत भारत एक्सप्रेस

गृह प्रवेश

- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (बिहार के 35600 लाभार्थी)
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (बिहार के 5920 लाभार्थी)

एनआरएलएम के अंतर्गत लाभों के वितरण

- बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत समूह स्तरीय संघों के लिए ₹500 करोड़ की सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) तथा पाँच सीएलएफ को चेकों की सुपुर्दगी

शुभारंभ

- राष्ट्रीय मखाना बोर्ड

परियोजनाओं के लाभ

- पूर्णिया हवाई अड्डे पर नए सिविल एन्क्लेव के विकास से क्षेत्र में हवाई यात्रा की माँग पूरी होगी
- नई लाइनों और रेलगाड़ियों के परिचालन से कुशल एवं किफायती रेल यात्रा के साथ यात्री और माल ढुलाई के लिए संपर्कता को बढ़ावा मिलेगा
- नए ताप विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन से घरेलू और औद्योगिक खपत के लिए विद्युत की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित होगी
- नए जलापूर्ति तंत्रों से संधारणीय जल प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा और जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल के कनेक्शन उपलब्ध कराने में तेजी आएगी
- अवरोधन एवं विपथन (आई एंड डी) तथा नए अपशिष्ट शोधन संयंत्र (एसटीपी) नदी के प्रदूषण को कम करेंगे तथा गंगा के पुनरुद्धार में सहायक सिद्ध होंगे
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के अंतर्गत 41,520 परिवार घर के मालिक बनेंगे
- गोजातीय लिंग-विभेदित वीर्य उत्पादन सुविधा से डेयरी किसानों की आय में वृद्धि होगी तथा उनका आर्थिक बोझ कम होगा
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत धनराशि के वितरण से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा और ग्रामीण निर्धन परिवारों/स्वयं सहायता समूहों का सशक्तिकरण
- मखाना उत्पादन उद्योग को बढ़ावा, जिससे इस क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र पर बिहार की पहचान को सुदृढ़ता मिलेगी

श्री नरेन्द्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री

द्वारा



सोमवार, 15 सितंबर, 2025



अपराह्न 03:30 बजे



पूर्णिया, बिहार

गरिमामयी उपस्थिति

श्री आरिफ मोहम्मद खान
राज्यपाल, बिहार

श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार

श्री मनोहर लाल
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य
तथा विद्युत मंत्री

श्री शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा
ग्रामीण विकास मंत्री

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा
पंचायती राज मंत्री

श्री किंजरापु राममोहन नायडू
केंद्रीय नागर विमानन मंत्री

श्री अश्विनी वैष्णव
केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

श्री सी. आर. पाटिल
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री

श्री सम्राट चौधरी
उप मुख्यमंत्री, बिहार

श्री विजय कुमार सिन्हा
उप मुख्यमंत्री, बिहार

श्री राजेश रंजन
संसद सदस्य (लोकसभा)

श्री विजय कुमार खेमका
विधायक, पूर्णिया



कार्यक्रम का सीधा प्रसारण डीडी न्यूज़ पर देखें

